



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : [www.mpmmandiboard.gov.in](http://www.mpmmandiboard.gov.in)

E-mail : [mdmandiboard@gmail.com](mailto:mdmandiboard@gmail.com)

Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी-5/2/एगमार्कनेट/2015-16/P-H/96/

भोपाल दिनांक 02/09/2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय,  
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषय:-भारत सरकार की “एगमार्कनेट” योजना क्रियान्वयन अंतर्गत।

संदर्भ:-1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के निर्देश क्रमांक 3893/PS/FWAD दिनांक 06 नवम्बर 2015।

2. श्री अविनाश केठे श्रीवास्तव, विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार का अर्द्ध0शा0 पत्र क्रमांक 16014/1/2015-M-II(Vol.III) दिनांक 16 नवम्बर 2015

-0-

उल्लेखित विषय में प्रथम संदर्भित पत्र के संलग्न सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार का अर्द्ध0शा0 पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2015 जो कि मुख्य सचिव, समस्त राज्यों को संबोधित है। द्वितीय संदर्भित पत्र सचिव, समस्त राज्यों को संबोधित है कि छाया प्रति सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है, का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।

उक्त पत्रों में एवं दिनांक 27 नवम्बर 2015 को भारत सरकार की नई दिल्ली से सम्पन्न विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक में प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड समस्त राज्यों से निम्नानुसार अपेक्षाओं को पूर्ण कर भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना का क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिये हैं :-

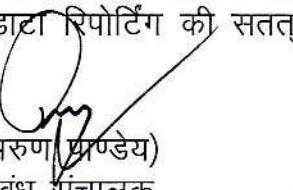
- (01) प्रदेश की एगमार्कनेट योजना अंतर्गत समस्त चयनित मण्डियों के द्वारा दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में उसी दिन यथा 12 घंटे के अंदर नियमित रूप से भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर रिपोर्टिंग की जाना सुनिश्चित करें।
- (02) प्रत्येक चयनित मण्डी समिति एगमार्कनेट पोर्टल पर अपनी जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगी कि भारत सरकार के निर्धारित User Manual-AGMARKNET Web Based Application में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये ही सर्वप्रथम डाटा रिपोर्टिंग की तिथि अर्थात् कार्य दिवस का चयन, जिन्स (Commodity) के नाम का चयन करने के उपरांत आवक (Arrival) की मात्रा मय निर्धारित Unit में दर्ज करने के उपरांत क्रमशः Variety अर्थात् किस्म का तथा Grade का चयन करेंगी तत्पश्चात् उस दिवस में जिन्स के न्यूनतम भाव (Minimum Price), अधिकतम भाव (Maximum Price), मॉडल भाव (Modal Price) का उल्लेख प्रति विंटल की दर के मान से किया जावे।

*Landeep*

- (03) मण्डी समिति का यह भी दायित्व होगा कि दैनिक आवक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इसमें संबंधित मण्डी के मुख्य प्रांगण सहित उप मण्डियों की तथा उपार्जन के दौरान मण्डी क्षेत्र में स्थापित क्य केन्द्रों की पूर्ण आवक की जानकारी का समावेश अनिवार्य रूप से किया जाये।
- (04) यदि किसी कार्य दिवस मण्डी में आवक निरंक है तो निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर स्पष्ट रूप से डाटा रिपोर्टिंग निरंक की जाना सुनिश्चित करायें।
- (05) यदि दैनिक डाटा रिपोर्टिंग के दौरान किसी कार्य दिवस में मण्डी के दैनिक मॉडल भाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम होना पाया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाये।

भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों की जानकारी अपने अंचल की योजना अंतर्गत चयनित समस्त मण्डियों के सचिव को अनिवार्य रूप से देवें एवं उसके अनुरूप भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने के साथ ही इस पर जानकारी डाटा रिपोर्टिंग की सतत मॉनिटरिंग भी करवायें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।



(अरुण पण्डेय)  
प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
*SL* भोपाल

क्रमांक / बी-5/2/एगमार्कनेट/2015-16/१५/९६२  
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल दिनांक ०२/१२/२०१५/१५  
नवम्बर/२०१५

- (01) निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 83, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की टीप क्रमांक 3893/PS/FWAD दिनांक 06 नवम्बर 2015 के संदर्भ में।
- (02) उप कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, 245, द्वितीय तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन-2 भोपाल (म0प्र0)।
- (03) श्री ए०एन०सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक एवं State Project Coordinator-Agmarknet, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विध्याचल भवन भोपाल (म0प्र0)।
- (04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... (म0प्र0) :- विषय संदर्भ में उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना का कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

197  
प्रबंध सचिवालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
su भोपाल

पुस्तकालय

SIRAJ H. A.  
SECRETARY

भा. सरकार  
 बृहि एवं कि = कल्याण मन्त्रालय  
 कृषि, संहकारिता & कैसान कल्याण विभाग  
 Government of India  
 Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare  
 Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare

मुख्य सचिव कार्यालय

CS/GEN/7611/2015-16

दिनांक 26/10/15

Dated 26/10/2015 (U.V.C.D.)

October 21, 2015.

भाषण संक्षेप

Subj.: 1. Request for prices of pulses and other essential commodities from Agmark and Department of Consumer Affairs Portal.

2. I am aware that the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare has started Agmark portal in which the data entry of the pulses arrived in the market is entered by the Staff Surveyors. Now the price of Urad on 19<sup>th</sup> & 20<sup>th</sup> October show a large number of quantities no report has been filed in the portal. It is requested that the Director of Agmark provides for several other commodities.

3. I would like to point out that in some of the mandis no transaction of pulses have taken place. However, in view of the above it is requested that the Director of Agmark is requested to make the information required be available in the portal so that the information required is available from the Agmark portal itself.

4. I am also informed that the prices of pulses may also be available on the website of Chief Secretary or Agriculture Firms or Level Commissions or so that corrective measures can be taken.

5. The Ministry of Consumer Affairs has been regularly in touch with the State governments for ascertaining the quantity of import of pulses through State Government or Central Government through State Government or Central Government of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In case of Delhi, the Central Government itself has set up a unit throughout outlets of Kendriya Bhawan. As per information given, no other State has resorted to this from the Department of Consumer Affairs. You will also note that the governments were allowed to set up State Level Commissions by taking assistance from the Government of the State. The 9% contribution was to come from a State. So far, however, only Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal and Delhi have taken advantage.

Office Krish Prakash, File No. : 23382651, 23388444 फैक्स नं. : 011-23386004

T.I.

प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया जवाब
23/10/2015
लिखा गया तिथि
लिखा गया दिनांक
लिखा गया संदर्भ

मंत्र. अमृत राहि विधायक चौक  
 दिनांक 23/10/2015  
 वार्ता  
 अपर विधायक (राम)

No. 3293 JPS/FWAD  
 Date 06/11/15

*Chief Minister's Secretariat*

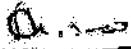
: 2 .

6. It is requested that Chief Secretaries of the above four States may kindly monitor the use of PSF set up in these States. The Chief Secretaries of other States are requested to urgently respond whether they would also like any funding from PSF.

7. Our total budget for PSF was Rs. 500 crores. Ministry of Finance have asked us to give revised estimates. For this, information has to be given to Ministry of Finance by 26<sup>th</sup> October, 2015. Based on the demands received from the State Governments, the Department will project its requirement under revised estimates. It is requested that the concerned Secretary may be asked to urgently communicate the requirement of funds from PSF of Government of India. However, we would like to reiterate that the State Government has to contribute 50% amount to this fund out of the State budget.

With regards,

Your sincerely,

  
(Shri R. Venkateswaran)

All Chief Secretary of States

Avinash K. Srivastava



31 Pwd-02  
विशेष सचिव  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
भारत सरकार  
Special Secretary  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
Department of Agriculture, Cooperation  
& Farmers Welfare  
Government of India

Dated: 16<sup>th</sup> November, 2015

D.O. No. 16014/1/2015-M-II (Vol.III)

Dear Secretary,

As you must be aware, the Government is closely monitoring the status of production and market arrivals of essential agri-commodities to ensure availability at affordable prices for consumers. For this purpose, the Government relies on the data on arrival and prices of agri commodities in wholesale markets across the country reported on the AGMARKNET Portal. ([www.agmarknet.nic.in](http://www.agmarknet.nic.in))

You will appreciate that availability of this data on Agmarknet is extremely crucial to any kind of assessment of the availability / price scenario for essential agri commodities. In fact Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (AC & FW), had also earlier vide his D.O letter of even number dated 21<sup>st</sup> October, 2015, addressed to Chief Secretaries, stressed the importance of regular reporting of data on arrival and prices on the AGMARKNET Portal and had also requested that the Director of Mandis be made responsible for ensuring correct and timely (within 24 hours) data entry on the portal.

Presently, the Government is undertaking creation of a buffer stock of pulses and procurement of Urad and Tur for this purpose is already underway. Given the importance of the matter, Secretary (AC & FW) vide his stated letter had infact requested that the prices of pulses be monitored at the level of Chief Secretary or Agriculture Production Commissioner / Development Commissioner so that corrective steps can be taken wherever possible.

*C. 809  
PDT  
DCM  
DCC  
DPM  
SAC  
27/11/15*  
You will appreciate the need to fool proof this data as it is being monitored at the highest level of the Government. I therefore request you for personal intervention and needful action/regular review to ensure correct data entry on daily basis on AGMARKNET Portal at the mandi level. Infact we would also welcome your suggestions, if any, on how data reporting on Agmarknet may be strengthened.

Yours Sincerely,

*AK Srivastava*  
(Avinash K. Srivastava)

Principal Secretary/ Secretary (Agriculture Marketing) of all the States/UTs

Copy to:- MD Mandi Boards of all the States/UTs (As per list attached).